भारतीय किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव का संक्षिप्त मूल्यांकन

प्राप्तिः 04.05.2026
स्वीकृतः 17.06.2026

37

प्रो (डॉ) लोकेश कुमार
(अर्थशास्त्र विभाग)
जे0एस0 कॉलेज,
सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर
ईमेलः *lokesheco11@gmail.com*

हरीश गिरी
शोध छात्र (अर्थशास्त्र विभाग)
जे0एस0 कॉलेज, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
ईमेलः *hkartik1979@gmail.com*

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 63.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। श्रम शक्ति का 47 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। जिस देश के अधिकांश लोग गांव में निवास करते हों, कृषि जिनकी जीविका के उपार्जन का मुख्य साधन हो वहां कृषि के समुचित विकास के बिना आर्थिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की जा सकती। भारत एशिया का विकासशील देश है जो नियोजन तथा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इसलिए जब तक ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा तब तक देश में पूरी तरह से समृद्धि नही आ सकती है और इस समृद्धि की धुरी है किसान। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरुरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में किसान किस तरह से अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक समस्याओं तथा इसके साथ ही खेती की समस्याओं से जूझते हुए अपने परिवार का भरण–पोषण करते है। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कितनी सार्थक है। इन्ही बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत विषय को मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया है।

1. प्रस्तावना

ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रुप में खेती से जुड़ा हुआ है। गांवों में रहने वाली आबादी में हर परिवार का कोई न कोई सदस्य खेती से जुड़ा हुआ है। यानी जब तक कृषि करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना अधूरी रहेगी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब किसान खाद, बीज, पानी, कृषि उपकरण आदि के लिए किसी पर आश्रित न होकर स्व–आश्रित होंगे तो उनमें कृषि के प्रति उत्साह रहेगा। इसी उत्साह को कायम रखने के लिए सरकार की ओर से समय–समय पर विभिन्न याजे नाएं चलायी गयी। हालांकि इन योजनाओं से किसानों को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया। किसान अपने हिसाब से जब चाहे तब

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.037

खेती से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कर सकें इसके लिए उन्हें पूंजी मुहैया कराने की जरुरत थी। ऐसी पूंजी, जो सस्ती ब्याज दर पर मिल सके और किसान अपनी सुविधा के अनुसार उस पूंजी की अदायगी भी कर सके। इस मुद्दे पर निरन्तर विचार–विमर्श चलता रहा और वर्षों के प्रयास के बाद यह पूंजी मिली किसान क्रेडिट कार्ड के रुप में।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य भारतीय किसानों को सस्ती और त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस अनुसंधान पत्र में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विकास, और समय–समय पर किए गए सुधारों का गहन अध्ययन किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की लगभग आधी आबादी की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। कृषि उत्पादन और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ समय–समय पर लागू की जाती रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसे 1998 में भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को त्वरित, सस्ती, और पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि और संबद्ध गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें।

2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का महत्व

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि और संबंद्ध गतिविधियों के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना किसानों को खेती के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसानों को अनौपचारिक ऋणदाताओं और साहूकारों की जकड़ से मुक्त करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किसान उच्च ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋणदाताओं से ऋण लेते हैं, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण मिलता है, जो न केवल सुरक्षित है, बल्कि ब्याज दरें भी अपेक्षाकृत कम होती हैं। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और वे अपने कृषि कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में समय–समय पर किए गए सुधारों ने इसके महत्व को और बढ़ाया है। 2004 में पशुपालन और मछली पालन को शामिल करने से लेकर 2018 में बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने तक, इन सुधारों ने योजना को अधिक समावेशी और व्यापक बनाया है। डिजिटल बैकिगं सुविधाओं का विस्तार भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे ऋण प्रक्रिया में तेजी और सरलता आई है। इन सुधारों ने किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारतीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया है।

3. अध्ययन की प्रासंगिकता

इस अध्ययन का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है, जिसमें इसके ऐतिहासिक विकास, सुधार, और वर्तमान स्थिति शामिल हैं। यह अध्ययन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी विश्लेषण करता है।

4. साहित्य समीक्षा

आर0 ओलकर (2012) ने भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्भव के कारणों का विश्लेषण किया। कृषि कार्यों के लिए ऋण के वितरण में जो समस्या थी, उसको दूर करने और बैंको द्वारा जो ऋण देने की व्यवस्था थी, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए रिजब बैंक आफ इण्डिया ने एक कमेटी का गठन किया, जो आर0वी0 गुप्ता कमेटी के नाम से जानी जाती है। इस कमेटी ने 1997 में कृषि ऋण के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं कृषि ऋण की वितरण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया। इस कमेटी की रिपोर्ट के परिणाम स्वरुप 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रति जागरुकता के रुप में मापी गयी। इस योजना में भूमि धारण के हिसाब से ऋण और ऋण में पर्याप्त लचीलापन था।

के0जी0 श्रीसागर (2014) ने अपने अध्ययन में सुझाव दिया कि भूमि पर स्वामित्व कृषि ऋण लेने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा इसके साथ ही साथ समूह में ऋण लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। भूमि पर स्वामित्व किसान क्रेडिट कार्ड धारक बनने के लिए एक महत्वपूर्ण दशा है।

शर्मा, आर. (2016), इस अध्ययन में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। शर्मा ने पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं।

सिंह, ए. (2018), इस शोध ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का अध्ययन किया। सिंह ने पाया कि डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, जैसे एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग, के माध्यम से किसानों को ऋण प्रक्रिया में सरलता और त्वरितता मिली है। इसने किसानों की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को बढ़ाया है और उनकी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

वर्मा, पी. (2020), वर्मा के अध्ययन ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण के पैटर्न का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि में समय के साथ वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है। वर्मा ने सुझाव दिया कि सरकार और बैंकिंग संस्थानों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विषेश अभियान चलाने चाहिए।

गुप्ता, एस. (2021), गुप्ता ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न सुधारों और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 2004, 2012, और 2018 में किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है और किसानों की विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की है। गुप्ता ने यह भी सुझाव दिया कि योजना में और सुधार की गुंजाइश है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।

मेहता, आर. (2023), इस हालिया अध्ययन ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वर्तमान स्थिति और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया। महे ता ने पाया कि योजना के तहत किसानों को त्वरित ऋण सुविधा मिल रही है, लेकिन ऋण प्रक्रिया की जटिलता और जागरूकता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने सुझाव दिया कि योजना की प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.037

एम0एस0 कलौर (2024) ने 25 गांवों का अध्ययन किया और पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बड़े किसानों के लिए ज्यादा मात्रा मेंवित्त दिया जा रहा है और वहाँ ज्यादा नगदी फसलों का उत्पादन हो रहा है और इसके साथ ही साथ खपत की आवश्यकता की पूर्ति भी के0सी0सी0 के माध्यम से की जा रही है। इस अध्ययन में इन्होने पाया कि किसानों में जो बिचौलियां हैं, वे भी के0सी0सी0 प्राप्त कर ले रहे हैं। सम्भवतः उत्पाद के बारे में जागरुकता का अभाव, बैंको की कागजी प्रक्रिया और बैंक कर्मचारियों के साथ व्यवहार आदि बाधाएं हैं, के0सी0सी0 धारक बनने में। के0सी0सी0 को वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण उत्पाद समझा जाने लगा है।

एस0एस0 संगवान (2024) ने अपने अध्ययन में किसान क्रेडिट कार्ड का वष्हद स्तर पर प्रभाव देखा तथा इसका प्रभाव कार्मशियल बैंको द्वारा प्रत्यक्ष रुप से पड़ा है। उन्होने पाया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ऋण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संगवान ने अपने अध्ययन में पाया कि फसलों के उत्पादन में केमिस्थि का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अपने अध्ययन में इन्होने पाया कि इस राज्य में कम कृषि भूमि वाले किसानों की संख्या ज्यादा हैं तथा उन तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पहुंच बहुत ही कम है। उन्होने अपने अध्ययन में पाया कि इस राज्य में बड़े कृषि भूमि वाले किसानों तक के0सी0सी0 की पहुंच बहुत ही अच्छी है। के0सी0सी0 धारकों का मानना है कि इस योजना में लोन के प्राप्त होने में निश्चित समय होता है और समय पर मिल जाता है। के0सी0सी0 शुरु हो जाने के बाद वाणिज्यिक बैंको ने अपने फसल ऋण में अपने शेयर को बढ़ा दिया लेकिन इसके साथ ही साथ ही केवल दो मुख्य फसलों के लिए लोन देती है।

5. संबंधित सिद्धांत और मॉडल

कई मॉडल और सिद्धांत किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए गए हैं। इन सिद्धांतों में कृषि वित्त, बैंकिंग सुधार, और विकास अर्थशास्त्र शामिल हैं।

6. अध्ययन के उद्देश्य

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना।
- योजना के विकास और सुधारों का विश्लेषण करना।
- योजना की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करना।

7. डेटा संग्रहण विधियाँ

अध्ययन के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। इसमें सरकारी रिपोर्ट, शोध पत्र, और अन्य संबंधित साहित्य शामिल हैं।

8. अध्ययन का पृष्ठभूमि

किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998–99 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने बजट सत्र के दौरान की। दरअसल सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों के बावजूद भी सूदखोरों का जाल टूट नहीं रहा था। किसानों को कई चरणों में पैसो की जरुरत पड़ती है। कभी बीज के लिए तो कभी खाद के लिए तो कभी खेत में पानी चलाने के लिए। ऐसे में किसान अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी सूदखोरों का बयाज नहीं चुका पाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सर्वे किया तथा ऐसी योजना लाने का प्रयास किया जिससे किसान को समय पर आसानी से कृषि ऋण

उपलब्ध हो सके और किसान सूदखोरों के जाल से बच सके। नाबार्ड और आर0बी0आई0 के सहयोग से 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई।

योजना के प्रारंभिक चरण में, किसान क्रेडिट कार्ड केवल फसल ऋण के लिए उपलब्ध था। किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार ऋण की एक निश्चित सीमा दी जाती थी, जिसे वे अपनी फसल की अवधि के दौरान उपयोग कर सकते थे। इस ऋण का उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक, और अन्य कृषि इनपुट्स के लिए किया जा सकता था। योजना का मुख्य लाभ यह था कि किसान अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार ऋण राषि का उपयोग कर सकते थे और उन्हें ब्याज केवल उपयोग की गई राशि पर ही देना होता था।

समय के साथ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार किए गए। 2004 में, पशुपालन और मछली पालन को योजना में शामिल किया गया, जिससे किसानों को विभिन्न कृषि संबंद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण मिलना शुरू हुआ। यह कदम किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद, 2012 में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को योजना में जोड़ा गया, जिससे किसानों को एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिला। इससे ऋण प्रक्रिया में और भी अधिक तेजी और सरलता आई।

2018 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए भी ऋण की सुविधा प्रदान की गई। इस विस्तार ने योजना को और अधिक समावेशी बनाया और किसानों को उनकी विविध कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की। इन सुधारों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। इन सभी सुधारों और विस्तारों के बावजूद, योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और ऋण प्रक्रिया की जटिल होना।

9. योजना के विकास की प्रक्रिया

1998 से लेकर अब तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कई सुधार किए गए हैं। शुरूआती चरण में यह योजना केवल फसल ऋण के लिए थी, लेकिन समय के साथ इसमें अन्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण की सुविधा जोड़ी गई।

9.1 योजना में समय–समय पर किए गए सुधार

- 2004: किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालन और मछली पालन को शामिल किया गया।
- 2012: किसानों को एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ दिया गया।
- 2018: योजना में बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों को भी शामिल किया गया।

9.2 योजना का विकास और सुधार प्रारम्भिक चरण: 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से फसल ऋण की सुविधा प्रदान की जाती थी।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.037

9.3 प्रमुख सुधार और उनके प्रभाव

- 2004 के सुधारः पशुपालन और मछली पालन को शामिल करने से किसानों को विविध कृषि गतिविधियों के लिए ऋण मिलना शुरू हुआ।
- 2012 के सुधारः डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से किसानों को त्वरित और सरल ऋण प्राप्त हुआ।
- 2018 के सुधारः बागवानी और अन्य गैर–फसली गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा ने किसानों की आय में वृद्धि की।

10. सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी नीतियों और बैंकों की सक्रिय भागीदारी ने इस योजना को सफल बनाने में मदद की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के सफल कार्यान्वयन में सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। इनमें समय–समय पर योजना के सुधार, नीतिगत दिशानिर्देश जारी करना, और किसानों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र ने इन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्राप्त हो सकी है।

2012 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को शामिल करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य किसानों को एटीएम कार्ड और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ देना था, जिससे ऋण प्रक्रिया सरल और त्वरित हो सके। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, और कई किसानों ने इन सुविधाओं का उपयोग करना शुरू किया। इससे न केवल ऋण प्रक्रिया में तेजी आई, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में किसानों का विश्वास भी बढ़ा। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के बारे में जानकारी बढ़ाई गई।

बैंकिंग क्षेत्र ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान किए, जैसे कि फसल ऋण, पशुपालन ऋण, और बागवानी ऋण। बैंकिंग क्षेत्र ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा, बैंकों ने किसानों को ऋण संबंधी जानकारी और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया।

सरकार और बैकिंग क्षेत्र के प्रयासों के परिणामस्वरूप, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए तालिका में 2012 से 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी गई ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया हैः

तालिका–1.1

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की भूमिकाः ऋण वितरण तालिका

क0सं0	वर्ष	ऋण राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
1	2012	150000	70
2	2013	160000	75
3	2014	170000	80
4	2015	185000	85
5	2016	200000	90
6	2017	220000	95
7	2018	250000	100
8	2019	280000	110
9	2020	300000	120
10	2021	320000	130
11	2022	350000	140
12	2023	3750000	155
13	2024	3850000	165
14	2025	400000	180

स्रोतः भारतीय कृषि मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट्स (2012–2025)

सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। इस योजना के तहत ऋण वितरण में लगातार वृद्धि ने किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है और उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि की है। सरकार की नीतिगत पहलें और बैंकिंग क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। इन प्रयासों ने भारतीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह तालिका भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए समग्र आंकड़ों का उल्लेख करता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी गई ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या को दर्शाता है।

11. परिणाम और विश्लेषण एवं सुझाव

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं। यह योजना किसानों को विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विकास महत्वपूर्ण रहा है। समय–समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाला है।

- एकत्रित डेटा का विश्लेषणः किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी गई ऋण की मात्रा और वितरण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि योजना ने किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है।
- समय–समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है।
- डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2026.v17i02.037

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को त्वरित और सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की है।
- समय–समय पर किए गए सुधारों ने योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाया है।
- योजना के समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे जागरूकता की कमी और प्रक्रिया की जटिलता।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
- ऋण प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
- किसानों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना में और सुधार किए जाएं।

संदर्भ

1. भारतीय रिजर्व बैंक (2020). किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
2. नाबार्ड (2019). कृषि वित्त और किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
3. कुमार, एस. (2018). भारतीय कृषि में वित्तीय सुधार. कृषि विकास जर्नल, 25(3), पृ0सं0–**45–60**.
4. शर्मा, आर. (2016). किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रभाव. बैंकिंग रिसर्च जर्नल, 14(2), पृ0सं0–**123–138**.
5. गोस्वामी, पी. (2015). कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुधारः एक विश्लेषण. विकास अध्ययन जर्नल, 30(4), पृ0सं0–**89–102**.
6. भारतीय कृषि मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट्स (2012–2022)
7. संगवान एस0एस0 (2024), ''इनोवेटिव लोन प्रोडक्ट्स एण्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट :: ए स्टडी आफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वीरु स्पेशल रिफ्रेन्स टू महाराष्ट्रा : इण्डियल जनरल आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स।
8. श्रीवास्तव के0के0 और सक्सेना पी0 (इन्स्टीच्यूशनल क्रेडिट एण्ड फ्राम सेक्टर एवीडेन्स फ्राम रुरल इण्डिया, इण्डियन जनरल आफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स (वाल्यूम–62, नं0–3, जुलाई से सितम्बर)
9. कलौर एम0एस0 (इम्पैक्ट आफ के0सी0सी0 आन फ्लो आफ क्रेडिट एण्ड रिपेमेन्ट रेट इन ए बैकवर्ड रिजन, ए केस आफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट बैंक इन सोरापुर तालुका, गुलबर्गा डिस्ट्रीक्ट, कर्नाटका इण्डियन जनरल आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स (वाल्यूम–62, नं0–3, जुलाई से सितम्बर)
10. ए0एम0 राजपूत तथा ए0आर0 वर्मा (2023), (क्रेडिट फाइनेन्सिंग आफ रिजनल रुरल बैक्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन होसंगाबाद, डिस्ट्रीक्ट इन मध्य प्रदेश), एकोनोमिक्स साहित्य भवन पब्लिकेषन आगरा।